27 जून, 2017

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की रियाध तथा जेरुशलम यात्रा: व्यावहारिक राजनीति की पुनर्स्थापना?

डॉ. अम्बरीन आघा

भूमिका

20 जनवरी 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प 20-21 मई 2017 को अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब गए। इसके बाद वो सीधे 22-23 मई को जेरुशलम तथा अधिग्रहित क्षेत्र की यात्रा पर गए। रियाध की दो दिवसीय महत्त्वपूर्ण यात्रा में राष्ट्रपति ट्रम्प ने उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया। सऊदी अरब अमेरिका सम्मेलन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अमेरिका सम्मेलन तथा अरब-इस्लामिक-अमेरिकी सम्मेलन जिसमें 55 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तीनों सम्मेलनों में राष्ट्रपति ट्रम्प ने अरब के नेताओं से द्विपक्षीय व्यपार संधि को मजबूत करने, आर्थिक विकास को गति देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर पहले से ही काफी आगे बढ़ चुके आपसी सहयोग अधिक बढ़ाने को लेकर बातचीत की।

मुख्यत: महत्त्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक सुरक्षा समझौतों एवं उनकी प्रगति के इर्द गिर्द रही। इस यात्रा का सीधा मतलब था कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति व्यावहारिक राजनीति की पक्षधर है। रियाध, जेरूशलम तथा वेस्ट बैंक की यात्रा को डोनाल्ड ट्रम्प की महत्त्वपूर्ण रणनीति के तौर पर देखा

जा सकता है, जहां उन्होंने सऊदी अरब के साथ महत्त्वपूर्ण समझौते किये। इजराइल तथा फिलिस्तीन के अलावा दूसरे अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की तथा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता बताई। राष्ट्रपित ट्रम्प ने अपनी पहली अधिकारिक विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रम्प की पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुने जाने के औचित्य पर सवाल उठना महत्त्वपूर्ण है, कि ट्रम्प ने अपनी पहली **विदेश यात्रा के लिए सऊदी को ही क्यों चुना?**

इस सवाल का जवाब देने के लिए शोध पत्र में पहले बात की जाएगी, कि रियाध में 3 सम्मेलनों से क्या निकला?

दूसरे भाग में राष्ट्रपति ट्रम्प की जेरुसलम यात्रा का विश्लेषण किया जाएगा। इजराइल की जनता को उनके संबोधन तथा बेथलहम में फिलिस्तीनी अधिकारी महमूद अब्बास से मुलाकात पर चर्चा होगी।

हर हिस्से में इन बैठकों के मुख्य मुद्दों तथा इस क्षेत्र के राजनीतिक आर्थिक एवं सुरक्षा परिदृश्य पर उनके प्रभाव की चर्चा व उनका आलोचनात्मक मुल्यांकन किया जाएगा।

खंड-1

राष्ट्रपति ट्रम्प की रियाध यात्रा

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि रियाध सम्मेलन, जोकि तीन सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा के मामलों में प्रगति के इर्द-गिर्द थी। सऊदी अमेरिकी सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को अधिक मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। सऊदी-अमेरिका द्विपक्षीय सम्मेलन से शुरू रियाध सम्मेलन दो बहुपक्षीय सम्मेलनों का भी समावेश था। तीनों सम्मेलनों का प्राथमिक उद्देश्य था सुरक्षा आधुनिकीकरण व्यापार संधियों को बढ़ावा देना, साथ में ऊर्जा समझौते तथा सबसे महत्त्वपूर्ण आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए उनकी प्रतिबद्धता दोहराया जाना। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच की रणनीतिक संधियों को मजबूती तो मिली ही, इसके आर्थिक तथा निवेश से जुड़े पहलुओं के

लिहाज से भी ये महत्त्वपूर्ण था। दोनों देशों के द्विपक्षीय लाभ के अलावा ध्यान देने की बात थी कि पहली विदेश यात्रा के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का रियाध को चुनना राजनीतिक तथा राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। सभी सम्मेलनों तथा जेरूशलम यात्रा पर चर्चा रियाध में इकट्ठा सभी पक्षों की समान हित चिंताओं तथा मुद्दों को रेखांकित करेगी।

1. **सऊदी अरब-अमेरिका सम्मेलन**

अपने रिश्तों को अधिक मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने आपसी विश्वास तथा साझा हितों पर आधारित आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प की रियाध यात्रा के पहले दिन 20 मई 2017 को अमेरिका तथा सऊदी ने 111 अरब यूएस डॉलर के बड़े हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किये। बताया जाता है कि ये हथियार सौदे समुद्री तथा तटवर्ती सुरक्षा में सुधार, वायुसेना के प्रशिक्षण तथा सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं संचार के विकास, मिसाइल तथा वायुरक्षा, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैँ। इस ऐतिहासिक हथियार सौदे के अलावा दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचे, संचार तकनीक तथा अन्य सैन्य हार्डवेयर के करीब 350 अरब यूएस डॉलर के व्यापार तथा निवेश समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

इन विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर से अर्थव्यवस्था की विभिन्नता तथा पेट्रो उत्पाद पर घटती निर्भरता का पता चलता है। इन मुद्दों पर सऊदी अरब के वाणिज्यिक तथा निवेश मंत्री डॉक्टर माजेद-बिन-अब्दुल्ला अल कसाबी ने कहा ''इन समझौतों की व्याप्ति तथा परिमाण तकनीकी, औद्योगिक निर्माण तथा एयरोस्पेस जैसे उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार की कहानी है, जिससे सऊदी अरब तथा अमेरिका में दो लाख पचास हजार रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते तथा संरक्षित होते हैँ।

शांतिपूर्ण मध्यपूर्व सुनिश्चित करने के लिए नए जोश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के नये युग के प्रारम्भ का स्वागत करने के लिए दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किये।

आर्थिक विकास व्यापार तथा कूटनीति इस क्षेत्रीय तथा वैश्विक साझेदारी के मुख्य बिंदु होंगे। स्ट्रैटेजिक विजन डिक्लेरेशन, जो सऊदी विजन 2030 को भी शान्ति देगा, रणनीतिक हिस्सेदारी मजबूत करने तथा देशों को उचित लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष-

- **द्विपक्षीय आर्थिक लाभ**: अमेरिका तथा सऊदी अरब की कंपनियों के बीच 350 अरब यूएस डॉलर के व्यापार तथा निवेश समझौते ने आर्थिक सहयोग, साझा हितों तथा आपसी विश्वास पर टिके दोनों देशों के संबंधों को अधिक मजबूत किया। इन सौदों में बहुवर्षीय लाइसेंस समझौते हैं। सीधे निवेश हैं तथा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग है, जो दोनों देशों के बीच 80 वर्षों के सम्बंधों मे सर्वाधिक हैं। इस यात्रा में कुल 40 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें औद्योगिक योजना विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए करीब 15 अरब यूएस डॉलर का निवेश भी है। समझौतों में रक्षा ऊर्जा तेल तथा गैस रसायन बुनियादी ढ़ांचा, तकनीकी एवं डिजिटल सॉल्यूशन, स्वास्थ्य सेवा तथा दवा निर्माण के क्षेत्र भी समझौतों में शामिल है। प्रेस से बातचीत में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा, "हमने 23 विदेशी निवेश तथा निर्यात लाइसेंस की घोषणा की, जिनमें 350 अरब अमेरिकी डॉलर के सीधे निवेश का ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त होगा।" अमेरिका तथा सऊदी अरब दोनों देशों के बीच निवेश तथा दूसरे दूसरे क्षेत्रों तक व्याप्त इन समझौतों से दोनों देशों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उदाहरणस्वरूप, सऊदी अरब को तकनीकी हस्तांतरण, उत्पादन तथा विनिर्माण उद्योग में स्थानीय सहभागिता बढ़ाना एक प्रमुख बिंदु है। इसके अलावा डेटा सेंटरों के जरिए तकनीकी क्षेत्र में निवेश, स्टार्ट अप्स तथा डिजिटाइजेशन के प्रयास 100 अरब यूएस डॉलर से अधिक के होंगे तथा यूएस एवं सऊदी अरब दोनों देशों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर आएंगे।

- **रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:** रणनीतिक साझेदारी की प्रक्रिया तय करने के लिए दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझा सलाह समूह गठित करने

की योजना बनाई है, जो साल में एक बार सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा करेगा, जिसमें मजबूत तथा एकीकृत सुरक्षातंत्र भी शामिल हैँ। अपने साझा सुरक्षा हितों के लिए दोनों देशों ने अतिवादी हिंसक संदेशों को रोकने, आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने तथा आधुनिक रक्षा सहयोग के लिए नई पहल की है। आर्थिक अंतर्निर्भरता की संधियों को मजबूती देने के लिए नए रक्षा सहयोग कार्यक्रम के तहत उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(a) रक्षा तथा हथियारों सम्बंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर- इसमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ भागीदारी में 150 S-70 ब्लैकहॉक हैलीकॉप्टरों को सऊदी अरब में असेंबल किये जाने की 6 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना शामिल है। यह कार्यक्रम तकनीक तथा कौशल हस्तांतरण से स्थानीय क्षमता को विकसित करने के सउदी अरब के विजन 2030 के लिए मददगार है। इससे सऊदी अरब में करीब 450 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

(b) अमेरिका के रक्षा तथा साइबर क्षेत्र की प्रमुख संस्था रेथियॉन देश में रक्षा, एयर स्पेस तथा सुरक्षा के स्थानीय सामर्थ्य के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इससे सऊदी अरब तथा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचने के साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।

(c) अमेरिका के रक्षा कॉन्ट्रैक्टर जनरल डायनामिक्स ने विजन 2030 के समर्थन में बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के क्षेत्रीयकृत डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण में वर्तमान एवं भविष्य के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत स्थानीय हिस्सेदारी पर सहमति दी है।

नए रक्षा सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य सऊदी अरब के विजन 2030 के अनुसार कार्रवाई योग्य साझेदारी, सहयोग तथा निवेश के अवसरों को विकसित करना है। इसका लक्ष्य है रोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा आर्थिक विविधता को प्रोत्साहित करना।

ट्रम्प ने विदेश दौरे के पहले गंतव्य स्थान के तौर पर रियाध को चुना। इससे स्पष्ट है कि रियाध, वाशिंगटन की नीतिगत प्राथमिकताओं में स्थित है। अब तक किसी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रथम विदेश दौरे के लिए इस देश का चुनाव नहीं किया था। हालांकि अपने गठन के बाद से ही सऊदी अरब इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है तथा ईरान में 1979 के दौरान आई इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होते गए हैं। निश्चित रूप से रियाध सम्मेलन में हुआ द्विपक्षीय 110 अरब अमेरिकी डॉलर का हथियार सौदा सैन्य सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक और परिपक्व रणनीतिक कदम है।

ट्रम्प की पहली यात्रा ईरान के साथ सऊदी अरब की पुरानी अदावत तथा अमेरिका के बैर को भी इंगित करती है। हलांकि मुख्य मुद्दा आईएसआईएस तथा इस्लामिक आतंकवाद को परास्त करना था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा तथा तेहरान को क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। ईरान द्वारा पैदा किये गए खतरों तथा धमकियों का विवरण देने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को रियाध तथा येरूशलम से बेहतर दूसरी जगह नहीं मिल सकती थी। दरअसल सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत हुए हथियारों के सौदे में ईरान को अलग-थलग कर देने का ट्रम्प की राजनीतिक योजना भी स्पष्ट दिख रही थी। राष्ट्रपति ट्रम्प की यात्रा के पहले दिन हुआ हथियार सौदा प्राथमिक रूप से "ईरान के घातक प्रभाव" को ही ध्यान में रखकर किया गया था। अमेरिका विदेश विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में बताया।

ईरान के घातक दुष्प्रभावों तथा धमकियों के मद्देनजर रक्षा उपकरणों का पैकेज सऊदी अरब तथा खाड़ी क्षेत्र की दीर्घकालीन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। इससे देश को अपनी सुरक्षा के साथ पूरे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के विरुद्ध मजबूती मिलेगी तथा अमेरिकी सेनाओं पर बोझ कम होगा।

द्विपक्षीय आतंकवाद विरोधी नीति को आगे बढ़ाते हुए रियाध तथा वाशिंगटन दोनों ने आतंक के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होने पर बल दिया। महत्त्वपूर्ण है कि दो फरवरी 2017 को ''नियर ईस्टर्न अफेयर्स'' के स्टेट डिपार्टमेंट ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी सरकार को 'क्षेत्रीय सहयोग एवं आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में

मजबूत सहयोगी' के तौर पर परिभाषित किया। इससे पहले 2 जून 2016 को प्रकाशित स्टेट डिपार्टमेंट कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2015 में कहा गया 'सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ सघन आतंकवाद निरोधी संबंधों को लगातार बनाए रखा है, सऊदी सीमाओं के भीतर तथा बाहर अमेरिका तथा सऊदी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के द्विपक्षीय साझेदारी की गई है तथा आईएसआईएल के विरोध के लिए वैश्विक गठबंधन का सक्रिय सदस्य रहा है।"

इस बीच अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने में सऊदी हीलाहवाली तथा कट्टरवादी इस्लामिक बोलबाले की ओर से आंखें बंद कर ली हैं। सऊदी नेताओं ने बरारबर विरोधाभासी गतिविधियां दर्शाई हैं। एक तरफ वहाबी इस्लाम को छोड़ने तथा पश्चिम के साथ अच्छे संबंध की चाहत, विशेषकर अमेरिका के साथ, दूसरी ओर ईरान के विरोध में अपनी सियासी तथा धार्मिक वैधता स्थापित रखने के लिए मौलवियों के कट्टरपंथी विचारों को सही ठहराना। क्षेत्र में अपनी धमक मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ऐसे स्पष्ट दिख रहे विरोधाभासी लक्ष्यों पर काम कर रहा है। इसपर अगर जल्द ध्यान ना दिया गया तो ये इस क्षेत्र के लिए घातक साबित हो सकता है।

2.जीसीसी-अमेरिका सम्मेलन 2017

सऊदी अरब तथा अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए जीसीसी नेताओं जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी तथा यूनाइटेड अरब अमिरात्स शामिल हैं, ने 21 मई 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा के साथ ही जीसीसी तथा वाशिंगटन के बीच अधिक मजबूत व्यापारिक संधियां बनाना इस उच्चस्तरीय वार्ता का केंद्र बिंदु था। इन नेताओं ने इससे पहले 21 अप्रैल 2016 को हुए सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा रणनीतिक हिस्सेदारी को अधिक गहरा बनाने की बात हुई। छह जीसीसी नेताओं के साथ हुई बैठक पहली खाड़ी-अमेरिकी बैठक नहीं थी। इससे पहले ओबामा के शासनकाल में 2015 तथा 2016 में भी दो बैठकें क्रमश: कैम्पडेविड तथा रियाध में हुई थीं।

जीसीसी-अमेरिका स्ट्रैटेजिक कोओपरेशन फोरम के साथ साझेदारी के तानेबाने को मजबूत करने के अलावा क्षेत्रीय तथा अतंरराष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता एवं खुशहाली, 2017 के सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य था। जारी बयान के अनुसार बैठक की रणनीतिक उपलब्धियों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **आतंकवाद**- बैठक में नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में संकट की जड़ को समाप्त करने तथा दाएश और अलकायदा को परास्त करने के प्रयासों को अधिक तेज करने के लिए त्वरित कदम उठाने की बात कही। आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखने के लिए पुन: कटिबद्ध होने, इसकी संस्थाओं को समाप्त करने, इसके सदस्यों को सजा दिलाने तथा इसके आय के स्रोत को समाप्त करने की बात भी बैठक में कही गई। आतंकवाद के खतरे से निपटने तथा आतंकवाद के अर्थ स्रोत से लड़ने में बुनियदी ढ़ांचे की सहूलियतों की सुरक्षा तथा सीमा तथा उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा भी सन्निहित है।

- **ईरान का विरोध**- नेताओं ने खतरे को उसके स्रोत पर ही समाप्त करने तथा प्राथमिक तौर पर ईरान की अस्थिरतावादी गतिविधियों का मुकाबला करने की जीसीसी देशों की क्षमता को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। क्षेत्रीय विवादों को शांत करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए नेताओं ने संप्रदायवाद तथा अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रीय तनावों को कम करने के लिए मिलजुलकर काम करने पर बल दिया। साथ ही ईरान के द्वेषपूर्ण हस्तक्षेप का भी विरोध किया। नेताओं ने क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में तेहरान के हस्तक्षेप की आलोचना की। तेहरान द्वारा बहरीन समेत जीसीसी देशों की प्रभुसत्ता के उल्लंघन तथा उसके नागरिकों में संप्रदायवाद के बैर को बढ़ावा देकर हिंसक उग्रवादियों को समर्थन, मुखबिरों को प्रशिक्षण, विस्फोटकों एवं हथियारों की तस्करी, अलगाववाद को हवा देने तथा विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा स्थिरता को खोखला करने की कोशिशों की भी आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने ईरान द्वारा लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागने पर गहरी चिंता

जताई तथा इस बात पर जोर दिया कि ईरान को परमाणु समझौता मान लेना चाहिए।

- **क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित करना**- क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने बाहरी खतरों से जीसीसी देशों को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने अधिक गहरे सुरक्षा सहयोग की प्रतिज्ञा की। क्षेत्र के सर्वाधिक बड़े विवादों को सुलझाने के लिए साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता में सीरिया, इराक तथा यमन के मुद्दे शामिल थे।

1. **सीरिया**- सभी नेताओं ने सीरिया की एकता, स्थिरता तथा राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने की अपनी वचनबद्धता बताई तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत के प्रयासों को समर्थन देने की बात कही। इसमें जिनेवा 1 विज्ञप्ति तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिजोल्यूशन (यूएनएससीआर) 2254 पर आधारित राजनीतिक हल ढूंढ़ना लक्ष्य था। उन्होंने सीरियाई शहरों से घेराबंदी हटाने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों तथा घेराबंद लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने, नागरिक इलाकों में बमबारी रोकने तथा हिरासत में लिये गए लोगों को छोड़ने की बात भी कही।

2. **इराक**- नेताओं ने बैठक में आशा जताई कि मोसूल को आजाद करने की प्रकिया से विस्थापित हुए लोग अपने शहरों- गांवों को लौट सकेंगे। साथ ही समग्र राजनीतिक पुनर्गठन की बात कही गई, जिससे इराक के लोगों को उनकी आशा के अनुरूप बिना बाहर किये एक दूसरे के करीब लाया जा सके।

3. **यमन**- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने तथा खाड़ी क्षेत्र की पहल तथा उसके कार्यकारी तंत्र के अनुसार एक राजनीतिक हल के महत्त्व पर बल देते हुए यमन की एकता, प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा आंतरिक मामलों में किसी तरह के हस्तक्षेप न करने की सभी नेताओं ने पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। नेताओं ने हूती सेना तथा उसके सहयोगियों को लगातार मिल रही हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने अलकायदा तथा दाएश के सहयोगी संगठनों या अरब प्रायद्वीप में आईएसआईएस से मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

- **आर्थिक संधियां मजबूत करना**- नेताओं ने जीसीसी द्वारा अपनाये विकास प्रारूप के अनुरूप व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा, उद्योग, प्रौद्योगिकी, कृषि, परिवहन तथा ढाचागत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को सहयोग देने तथा मजबूत करने पर सहमति जताई।

- **पहली खाड़ी-अमेरिकी बैठक प्रगति की समीक्षा**- बैठक में उपस्थित नेताओं ने पहली खाड़ी-अमेरिकी बैठक के निर्णयों को लागू करने के लिए गठित कार्य समूहों की उपलब्धियों की समीक्षा की, जिनमें बैलिस्टिर मिसाइल से रक्षा, हथियारों का स्थानांतरण, प्रशिक्षण, आतंकवाद से मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ढांचागत सुरक्षा तथा क्षेत्र में ईरान के दोषपूर्ण हस्तक्षेप को रोकना शामिल था। नेताओं ने दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षामंत्रियों की बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर निकटवर्ती सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही इसी प्रारूप में प्रतिवर्ष बैठकों में लिये गए निर्णयों तथा पहल की प्रगति समीक्षा किये जाने पर सहमत हुए।

जीसीसी-अमेरिका सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने "अरब-नेटो" के रूप में सुन्नी देशों के गठबंधन के विचार को प्रोत्साहित किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ईरान तथा आईएसआईएस का मुकाबला करना है। ईरान को खरी-खोटी सुनाते हुए ट्रम्प ने संप्रभु ईरान देश को एक ऐसे इस्लामिक स्टेट का दर्जा दिया, जो राष्ट्र की भूमिका नहीं निभा रहा है। "अरब अथवा सुन्नी नेटो" के गठन का आह्वान बिल्कुल अनुपयुक्त तथा अतिसाधारण रूप में, विशेषकर अरब देशों की आपसी खींचतान को देखते हुए कहा गया। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे गठबंधन की घोषणा करते ही इसमें बिखराव के संकेत दिखने लगे। कतर तथा सऊदी अरब समेत खाड़ी क्षेत्र के पांच पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक दरार ईरान को घेरने के लिए 'एकीकृत सुन्नी देशों का गठबंधन' बनाने के ट्रम्प के प्रयास को तगड़ा झटका है।

महत्त्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा प्रभावी तथा ताकतवर आईएसआईएस से है, जो वहाबी दर्शन का अनुसरण करनेवाला एक आतंकी संगठन है। वहाबी इस्लाम की ही एक प्रशाखा है जो अठारहवीं शताब्दी में सऊदी अरब में विकसित हुई तथा वहां यह आज भी अस्तित्व में बना हुआ है। ऐसा करते हुए ट्रम्प ने पश्चिम एशिया के प्रति अमेरिका की पुरानी नीति का अनुसरण किया, जिसमें अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रहे तथा ईरान के विरुद्ध हमलावर तेवर रखे गए।

जॉर्ज बुश जैसे अपने पूर्ववर्ती नेताओं की तर्ज पर ईरान को आड़े हाथों लेते हुए ट्रम्प ने ईरान को आतंक का प्रायोजक देश करार दिया। साथ ही उन्होंने सऊदी अरब द्वारा मुस्लिम विश्व में दशकों तक फैलाये गई असहिष्णुता तथा अतिवाद की भी उपेक्षा की, जिसके मूल में वहाबी शिक्षा थी। दूसरी ओर सऊदी अरब आतंकवाद के विरोध लड़ाई में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी भी है। इस यात्रा का लक्ष्य सुन्नी देशों को ईरान तथा आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका तथा रियाध के साथ लामबंद करना था। 1943 में अमेरिका-सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक साझेदारी ध्यान देने योग्य है। वस्तुत: रियाध के साथ सैन्य गठजोड़ बनाने में ट्रम्प अपने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों का ही अनुसरण कर रहे हैं। बराक

ओबामा के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने रियाध को पूरी उदारता से हथियार सप्लाई किये थे। वाशिंगटन के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी से जुड़े विलियम हार्टग की रिपोर्ट के अनुसार ओबामा प्रशासन ने 42 अलग-अलग सौदों में सऊदी अरब को 115 अरब से ज्यादा के हथियार, दूसरे सैन्य साजो सामान तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराए थे। यह पिछले 71 वर्षों में किसी भी अमेरिकी प्रशासन से मिली सर्वाधिक मदद है। इससे सऊदी अरब के मामले में ओबामा का दोहरा रवैया स्पष्ट है, यानी सऊदी अरब में प्रचलित इस्लाम के अतिवादी स्वरूप की प्रखर आलोचना करते हुए उसी देश के साथ बड़ी सैन्य साझेदारी करना। दरअसल पश्चिम एशिया के मामले में ओबामा की कभी आगे, कभी पीछे वाली अमेरिकी नीति का अनुसरण करते हुए ट्रम्प द्वारा किया गया हथियार सौदा सैन्य सहयोग वाले दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाएगा।

(3) अरब-इस्लामिक-अमेरिकी शिखर सम्मेलन:

अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के रियाध दौरे के दूसरे दिन 21 मई को ऐतिहासिक अरब-इस्लामिक-अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के बढ़ते खतरों तथा हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए अमेरिका तथा मुस्लिम देशों के बीच सहिष्णुतापूर्ण सामंजस्य पैदा कर एक मजबूत तथा प्रभावी सुरक्षा साझेदारी विकसित करना। वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने रियाध में ग्लोबल काउंटर एक्स्ट्रिमिज्म सेंटर का उद्घाटन किया। किंग अब्दुल अजीज़ कॉन्फ्रेंस सेंटर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने 55 मुस्लिम राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित किया ताकि "इस्लामिक उग्रवाद के संकट तथा इस्लामिक आतंकी संगठनों के उत्प्रेरकों" पर चर्चा की जा सके। अरब-इस्लामिक-अमेरिकी सम्मेलन में एक-दूसरे से जुड़ी पांच महत्त्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आईं, जो निम्नलिखित हैं:

- **आतंकवाद से मुकाबला तथा मध्य-पूर्व रणनीतिक गठबंधन:** नेताओं ने अपने देशों में हर तरह से आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके अन्तर्गत उन्हें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने, उसकी फंडिंग के स्रोतों को रोकने तथा सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि आतंकवाद

तथा उससे पनपनेवाले अपराधों को रोका जा सके। नेताओं ने इसके लिए मध्य-पूर्व रणनीतिक गठबंधन बनाने के विचार की सराहना की। रियाध इसकी मेजबानी करेगा तथा इसमें शामिल होनेवाले सभी देश अपने क्षेत्र तथा दुनिया में शांति एवं सुरक्षा के लिए योगदान देंगे, जिसमें कई देश इस क्षेत्र तथा दुनिया में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने में योगदान देने के लिए भाग लेंगे। ये गठबंधन तथा इसमें शामिल होनेवाले देशों की भागीदारी की घोषणा 2018 में पूरी हो जाएगी।

- **उग्रवादी विचारधारा से निपटने के लिए ग्लोबल सेंटर की स्थापना:** ये सेंटर मुख्य तौर पर उग्र विचारधारा, मीडिया तथा डिजिटल उग्रवाद पर नज़र रखेगा तथा उससे निपटेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने तथा आवश्यकता पड़ने पर आतंकी संगठनों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को मदद देने के लिए 34,000 सैनिकों का रिजर्व फोर्स मुहैया कराने को तैयार इस्लामिक देशों का नेताओं ने स्वागत किया है। इसके अन्तर्गत एक टेरेरिस्ट फाइनेंसिंग टारगेटिंग सेंटर भी बनाया जाना है जो आतंकियों की फंडिंग पर नज़र रखकर उसे समाप्त करेगा। सऊदी अरब के रियाध में ही ये सेंटर होगा।
- **सह-अस्तित्व तथा रचनात्मक सहिष्णुता को प्रोत्साहन देने के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एसडीपी) पर जोर:** सहयोगी देशों ने सार्थक तथा गंभीर सांस्कृतिक संवाद को बड़े स्तर पर लाने के महत्त्व पर जोर दिया, जो इस्लामिक मजहब की सहिष्णुता तथा संयम के साथ हिंसा से उसकी दूरी भी दर्शाता है। नेताओं ने इस दौरान एसडीपी के लिए साझा सहयोग पर भी बल दिया ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके तथा उन्हें एक सुरक्षित, स्थिर तथा बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। ये माहौल ही इनक्यूबेटर की तरह युवाओं को भटकानेवाले अतिवादी विचारों से बचाने का काम करेगा।
- **अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप तथा सांप्रदायिक एजेंडे का सामना:** नेताओं ने देशों के बीच वर्तमान सहयोग, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों पर आधारित सम्बंध, दूसरे देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, उनकी स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता के सम्मान पर बल दिया। नेताओं ने ईरानी शासन

की लड़ाकू प्रवृति तथा अंतरराष्ट्रीय कानून तथा सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए दूसरे पड़ोसी देशों के घरेलू मामलों में लगातार हस्तक्षेप की निंदा की तथा ये स्पष्ट किया कि वो ईरानी शासन के पड़ोसी क्षेत्रों तथा दुनिया की सुरक्षा पर खतरा बननेवाली हरकतों एवं आतंकवाद व उग्रवाद को लगातार समर्थन देने के विरुद्ध सख्त कदम उठाएंगे।

- **समुद्री लुटेरों से रक्षा तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा:** नेताओं ने क्षेत्रीय जल सीमा, बंदरगाह तथा समुद्री परिवहन के दौरान होनेवाले व्यवधानों को दूर करने, सुरक्षा देने तथा समुद्री लुटेरों से रक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई के महत्त्व पर भी जोर दिया। इससे न सिर्फ वाणिज्यिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ता है बल्कि देशों की आर्थिक विकास दर भी प्रभावित होती है।

सऊदी अरब के अपने पिछले दौरे में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के वायदे को पूरा करते हुए ट्रम्प ने अरब-इस्लामिक-अमेरिकी शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन 21 मई 2017 को रियाध में 'ग्लोबल सेंटर फॉर कॉमबैटिंग एक्स्ट्रिमिज्म' के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान रणनीतिक गठबंधन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अरब, इस्लामिक वर्ल्ड तथा अमेरिका के बीच साझेदारी के क्षेत्र में एक देख-रेख तंत्र भी विकसित किया गया। इसके अन्तर्गत नेताओं ने अपने देशों में संबंधित विभागों की मंत्रालय समितियां तथा उपसमितियां बनाकर उन्हें रियाध की घोषणाओं को लागू करने का जिम्मा सौंपा, ताकि वो उनके सीधे संपर्क में रह सकें तथा बैठकों एवं चर्चाओं के माध्यम से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर सकें।

अमेरिका-सऊदी अरब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तरह ही ट्रम्प ने अरब-इस्लामिक-अमेरिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेनेवाले मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो आतंकवाद से लड़ने तथा ईरान का सामना करने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। यहां स्पष्ट दिखा कि कैसे रियाध, तेहरान तथा बड़े क्षेत्रीय राजनीति को लेकर वाशिंगटन के दृष्टिकोण में लगातार परिवर्तन आया है।

1973 के तेल प्रतिबंध तथा 11 सितंबर 2011 के आतंकी हमलों में 15 सऊदी नागरिकों की संलिप्तता को लेकर प्रारम्भिक दौर में उत्पन्न तनाव के बावजूद अमेरिका-सऊदी अरब गठबंधन अंजाम तक पहुंचा।

21 मई को अरब-इस्लामिक-अमेरिकी शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने मुख्य रुप से इराक, सीरिया तथा यमन में दिखने वाले 'ईरानी विस्तारवाद' के विरुद्ध एक क्षेत्रीय ढांचा तय करना आवश्यक बताया।

लेबनान से लेकर इराक तथा यमन तक ईरान न सिर्फ आतंकवादियों, सैन्य लड़ाकों तथा अन्य उग्रवादी संगठनों को ट्रेनिंग देता है, बल्कि धन तथा हथियार उपलब्ध कराकर विनाश तथा अराजकता का साम्राज्य फैला रहा है। दशकों से ईरान सांप्रदायिक हिंसा तथा आतंकवाद की आग को हवा देता रहा है। जब तक ईरानी शासन शांति के लिए पहल नहीं करता तथा आतंकवाद के लिए फंडिंग बंद नहीं करता, तब तक सभी राष्ट्रों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर ईरान का का बहिष्कार करना होगा ताकि एक दिन ईरान की जनता को एक योग्य सरकार मिल सके।

ईरान को अलग-थलग करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ ट्रम्प ने पश्चिमी एशियाई देशों से साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। ईरान के प्रति ट्रम्प का ये रुख नया नहीं है। पूर्व शासकों का रवैया भी ईरान के प्रति इतना ही सख्त रहा है। आमतौर पर ये ट्रम्प की ओबामा प्रशासन के ईरानी दमनात्मक नीतियों से अलग दिखता है। हालांकि इस तरह की दमनात्मक नीति का दायरा 14 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किए गए परमाणु समझौते तक ही सीमित था, लेकिन जिसने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंधों को प्रोत्साहन देते हुए ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगू बना दिया। हालांकि विदेश नीति के तौर पर ओबामा का परमाणु समझौता अमेरिकी-ईरान शीत युद्ध पर विराम नहीं लगा सका तथा तेहरान भी वाशिंगटन के पुराने राजनीतिक संदेह के घेरे में ही बना रहा।

इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए 20-21 मई को रियाध शिखर सम्मेलन में, अपने कट्टर दुश्मन ईरान के प्रति अमेरिका तथा सऊदी अरब नेतृत्व का रुख काफी आक्रामक दिखा। ईरान-सऊदी अरब के बीच तनाव दशकों से इस क्षेत्र पर भारी पड़ता रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, किंग सलमान बिन अब्दुल-अजीज अल सऊद ने अपने भाषण में ईरान पर दशकों से आतंकवाद फैलाने का

आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाने की बात कही, तथा इसी स्वर में राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी ईरान की निंदा की।

<u>खंड II</u>

राष्ट्रपति ट्रम्प की यरूशलेम तथा वेस्ट बैंक यात्रा

अपनी पहली विदेशी यात्रा के दूसरे चरण में, राष्ट्रपति ट्रम्प यरूशलेम गए तथा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद वो वेस्ट बैंक गए जहां बेथलेहम में उन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इजराइल तथा फिलीस्तीनी अथॉरिटी की यात्रा के दूसरे तथा अंतिम दिन राष्ट्रपति ट्रम्प ने तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों तथा चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की।

1. अमेरिका-इजराइल गठबंधन
2. इजराइल-फिलिस्तीन के बीच शांति
3. आईएसआईएस का खात्मा
4. ईरान तथा उसके क्षेत्रीय विस्तारवाद का सामना

यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल की यात्रा के दौरान ट्रम्प ने इजराइल तथा फिलिस्तीनियों के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि- "मैंने सुना है कि ये काफी कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे प्राप्त कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।" साथ ही ट्रम्प ने “इज़राइल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्ती के अटूट सम्बंध” की प्रतिबद्धता दोहराई।

ट्रम्प ने कहा कि- “हम दोस्त से कहीं अधिक हैं। हम अच्छे सहयोगी हैं। हमारे सामने कई अवसर हैं, लेकिन हमें उन अवसरों को साथ मिलकर हासिल करना होगा। इस मौके का लाभ लेने के लिए हमें समृद्ध होना होगा, आतंकवाद के शैतान को हराना होगा तथा ईरान के खतरे का मुकाबला करना होगा, जो क्षेत्र में हिंसा तथा दुख की धमकियां दे रहा है।”

उसी दिन जेरूसलम के इज़राइल संग्रहालय में श्रोताओं को संबोधित करते हुए, ट्रम्प ने अमेरिका तथा इज़राइल के बीच अटूट सम्बंध कायम करने पर बल दिया तथा ईरान की धमकियों पर भी टिप्पणी की। ट्रम्प ने इजराइल को आश्वस्त किया, "मैं आपसे वादा करता हूं: अमेरिकी प्रशासन हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा... तथा ईरान के नेताओं की लगातार इजराइल के विनाश की मंशा... डोनाल्ड जे ट्रम्प के रहते कभी पूरी नहीं होगी, मेरा विश्वास करें।" तेहरान के परमाणु ताकत बनने पर अरब देशों तथा इजराइल की “साझा चिंता” पर राष्ट्रपति ट्रम्प ने संकेत दिया कि ये इजराइल तथा फिलिस्तीन को एकजुट करने में मददगार साबित होगा। तेहरान के आतंकवादियों तथा सैन्य लड़ाकों को दिए जानेवाले सैन्य तथा वित्तीय मदद रोकने की मांग के साथ ट्रम्प ने 23 मई को तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ओबामा के परमाणु समझौते के बारे में बताते हुए भरोसा दिया कि ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता।

उसी दिन, वेस्ट बैंक पहुंचने पर ट्रम्प ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बेथलेहेम में मुलाकात की। यहां उन्होंने फिर इजराइल तथा फिलिस्तीनियों के बीच शांति कायम करने के लिए "सब कुछ करने" का वचन दोहराया। अब्बास के राष्ट्रपति भवन में संवाददाता सम्मेलन के दौरान, ट्रम्प ने कहा कि "हमें रोजाना शांति का एक विकल्प तैयार रखना चाहिए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यहां के युवा, यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। राष्ट्रपति अब्बास ने भी ट्रम्प को उसी गर्मजोशी के साथ शांति कायम करने में फिलिस्तीन के सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति अब्बास ने इस बात पर बल दिया कि इजराइल के साथ फिलिस्तीन का संघर्ष धर्म आधारित नहीं, बल्कि व्यवसाय तथा उपनिवेशीकरण से जुड़ा है। अब्बास ने कहा कि फ़िलिस्तीन, इज़राइल के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने अमेरिका तथा इजरायलियों के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, “ये महत्त्वपूर्ण है कि फिलिस्तीनी स्वतंत्र हों ताकि फिलिस्तीन तथा इजरायली बच्चों को एक सुरक्षित, स्थिर तथा समृद्ध भविष्य दिया जा सके। ट्रम्प ने कहा कि

अगर इजराइल तथा फिलिस्तीन शांति बहाल करते हैं तो ये उनके लिए एक विशेष उपलब्धि होगी तथा इससे मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच शांति बनाने की दिशा में सभी पहलुओं पर प्रतिबद्धता दोहराने को लेकर येरूशलम तथा बेथलहम यात्रा सार्थक साबित हुई, जिसे ट्रम्प ने एक बार असाधारण समझौता कहा था। हालांकि सवाल अब भी है कि क्या ट्रम्प ये असाधारण समझौता करवा सकते हैं? अगर हां, तो इस समझौते के परिणाम क्या होंगे? पश्चिम एशिया में राष्ट्रपति ट्रम्प सांप्रदायिक मुश्किलों से कैसे निपटेंगे?

रियाध से येरूशलेम तक ईरान विरोधी लहर ट्रम्प के दौरे पर हावी रही। 22 मई, 2017 को येरूशलेम में ट्रम्प ने ईरानी शासन के खतरे से आगाह करते हुए उन्हें उकसाया। येरूशलम यात्रा के दौरान ट्रम्प ने क्षेत्र में, विशेषकर इराक तथा सीरिया में ईरान के बढ़ते दबदबे को लेकर अपने विचारों को दोहराया तथा ईरान के राजनीतिक उलझाव के बारे में इजरायली राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन से चर्चा की। ईरान से मिलनेवाली धमकियों पर जोर देते हुए ट्रम्प ने इजराइल के करीबी होते अरब देशों की चिंता पर चर्चा की। ट्रम्प ने राष्ट्रपति रिवलिन को बताया कि ईरान के साथ जो हुआ उससे मध्य पूर्व के कई हिस्सों की इजराइल से नजदीकियां बढ़ी हैं।

इसके अलावा, ट्रम्प के असाधारण (इजराइल-फिलिस्तीन) समझौता लागू करने की घोषणा उल्लेखनीय थी। ये अलग बात है कि कोई ठोस उपाय की पहचान नहीं हो सकी। शांति प्रक्रिया को देखते हुए दृष्टिकोण तथा कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प के तर्क तथा प्रतिबद्धता में अस्पष्टता साफ दिखाई देती है, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं। दरअसल, कार्यालय संभालने के बाद से ही इजराइल-फिलिस्तीन समझौते के भविष्य को लेकर पर ट्रम्प की योजना स्पष्ट नहीं रही है। राष्ट्रपति पद संभालने के महज एक महीने बाद ही 15 फरवरी, 2017 को ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि- "मैं दो देशों तथा एक देश की तलाश कर रहा हूं, तथा मुझे वो पसंद है जिसे दोनों पार्टियां चाहती हैं... मैं किसी एक के साथ रह सकता

हूं।" इस मुद्दे पर उनकी अस्पष्टता बरकरार है तथा राष्ट्रपति ट्रम्प अभी भी दो राज्य बनाम एक राज्य समाधान को लेकर वो अनिश्चित ही दिखते हैं।

हालांकि इस दुविधा के बावजूद ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया कि वो समझौता चाहते हैं। फिलिस्तीन शांति सौदे की मध्यस्थता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "मैं वो सब करुंगा जो मैं कर सकता हूं"। शासन के शुरुआती दौर में राष्ट्रपति ट्रम्प की अस्पष्टता एक सचेत विकल्प हो सकती है, अगर उसे उसी रुप में छोड़ दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी का भी पक्ष लेने से इंकार कर दिया। समझौते के मुद्दे पर भविष्य में किसी कार्रवाई को लेकर इस दौरे में भले ही बहुत दम नहीं दिखा, लेकिन कुटनीतिक तौर पर दो संघर्षशील पक्षों तक पहुंचने में ये दौरा लाभदायक साबित हुआ जो सहानुभूतिपूर्ण तथा नरम रुख से स्पष्ट था।

इतना ही नहीं, अगर हम इसे इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष से अलग करके देखें तो पाते हैं कि पश्चिमी एशिया में अस्थिरता, अराजकता तथा हिंसा से भरी सांप्रदायिकता, फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया के बाद इस क्षेत्र की एक विनाशकारी क्षमता है। राजनीतिक तौर पर ये कहना आसान है कि इजराइल-फिलिस्तीन शांति समझौता पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति बहाल कर सकता है। इसका एक उदाहरण यमन में जारी वो युद्ध है, जहां सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हौथी शिया विद्रोहियों के विरुद्ध सरकार के राष्ट्रपति एबद रबबो मंसूर हादी को समर्थन दिया। यमन में तीन साल से जारी युद्ध के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना ये स्पष्ट करता है कि सत्ता संघर्ष, क्षेत्रीय वर्चस्व की चाह सऊदी अरब तथा उसके दुश्मन ईरान के बीच कट्टर विरोध पश्चिम एशियाई क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित करते हैं, जो रियाध तथा तेहरान के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में प्रचलित है। वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रम्प के रियाध तथा येरूशलेम के शुरुआती दो दौरे राजनीतिपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर थे, जो पश्चिम एशिया को क्षेत्रीय संकट से उबारने में बड़ी चुनौती साबित हुआ।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति ट्रम्प की रियाध तथा येरूशलेम यात्रा में राजनीतिक तथा रणनीतिक मुद्दे हावी रहे, जिनमें पहला था ईरान का सामना करना तथा दूसरा आतंकवाद तथा विशेषकर आईएसआईएस से निपटना। दोनो ही विषय सार्वजनिक सहयोग तथा

साझा चिंताओं के तौर पर सामने आए, जिसे राष्ट्रपति ट्रम्प ने 20-21 मई को रियाध में तथा 22-23 मई को इजराइल में दोहराया।

रियाध जाने की ट्रम्प की कुटनीतिक मंशा का जवाब पश्चिम एशियाई क्षेत्र की तेजी से बदलती राजनीति में मिल जाता है, जहां राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभावों के विस्तार को रोकने तथा उसे जवाब देने के उद्देश्य से संभावित सऊदी-इजराइल गठबंधन का समर्थन करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ, इस यात्रा का लक्ष्य सहमति के रुप में भी समझा जा सकता है जहां राष्ट्रपति ट्रम्प इजराइल समेत मुस्लिम अरब देशों को समर्थन देने के दौरान इजराइलियों तथा अमेरिकियों को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इज़राइली नेतृत्व की तरह ही अरब भी पश्चिम एशिया में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा कड़ी है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के रियाध तथा यरूशलेम के चार दिवसीय यात्रा के दौरान नेताओं के वक्तव्यों ने ईरान के विरुद्ध एक धूरी के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसके राजनीतिक परिणाम भी दिखे। ईरान से होनेवाले खतरों पर जोर देते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने शायद एक रणनीतिक गठबंधन का माहौल बना भी लिया हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस्लामिक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक अमेरिकी खाड़ी-इजरायली गठबंधन तभी एक रचनात्मक नतीजे पर पहुंचेगा जब संबंधित शक्तियों के साथ ईरान भी उसमें शामिल हो। ईरान को क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने का दृष्टिकोण एक गलत अनुमान है तथा गंभीर भी, जो आने वाले दशकों में पश्चिम एशियाई देशों को नुकसान पहुंचाएगा।

वो कठोर इस्लामिक विरोधी बयानबाजी, जो उनके चुनाव प्रचार के दौरान एक अहम हिस्सा थे, उससे बिलकुल अलग उन्होंने दूसरों को व्याख्यान न देने तथा उन्हें जीने का तरीका न बताने या फिर पूजा करने के तरीकों पर न बोलने का वचन दिया। संयोग से तमाम बैठकों तथा सम्मेलनों में ट्रम्प के भाषण काफी मित्रवत तथा परस्पर विरोधी रहे। इसमें पहला संबोधन मेजबान देशों के लिए था तो दूसरा ईरान की तरफ जिसमें क्षेत्रीय तथा वैश्विक राजनीति में तेहरान को अलग करने पर बल दिया गया। पश्चिम आतंकवाद तथा नागरिकों की हत्या के लिए जीरो टॉलरेंस पर एक निर्णायक राय देते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के भविष्य में पश्चिमी एशिया में ईरान की भूमिका को कम आंकते हुए ईरान का

विरोध किया। सऊदी अरब तथा इजराइल की तरफ झुके पूर्वाग्रह को देखते हुए ये पूछना आवश्यक है कि क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक को बढ़ावा देना तथा दूसरे को अलग छोड़ने वाले विभेदकारी दृष्टिकोण क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता स्थापित कर पाएंगे?

सऊदी अरब के साथ रणनीतिक गठबंधन पर विश्वास रखते हुए ट्रम्प ने देश के साथ उन सम्बंधों से इंकार किया जो धर्मांतरण करनेवाले पादरियों से तथा वहाबिज्म (इस्लाम का अतिवादी रुप जो आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस तथा अल कायदा को प्रेरित करता है) का प्रचार करनेवालों से साझा करता है। इसकी जानबूझकर उपेक्षा करने की कीमत इस्लामिक उग्रवाद को समाप्त करने के बड़े उद्देश्य से समझौते के रुप में चुकानी पड़ती है। आतंक के विरुद्ध अपने वैश्विक युद्ध में, संयुक्त राज्य अमेरिका एक को आगे बढ़ाकर दूसरे से युद्ध कर रहा है। वहां शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर उन्हें सुन्नी सऊदी तथा शिया ईरान के रूप में विभाजित कर रहा है। ये जानना काफी महत्त्वपूर्ण है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक विशेष तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना सिसफैन अभ्यास की तरह है।

आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा कूटनीति के समग्र दृष्टिकोण के बिना उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई आधी जीत के बराबर है। कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया, जैसा रियाध तथा येरूशलम यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प का दिखा, उपरी तौर पर समस्या का समाधान करेगा। विदेश नीति के अन्तर्गत किसी देश तथा व्यवहारिक राजनीति के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है ताकि देश तथा राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके।

** डॉ. अम्बरीन आगा विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं*

** डिस्क्लेमर:उपरोक्त विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।*